जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 156 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 10 अप्रैल, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

पायलट को और अधिक महत्व देने की राह में एक और मजबूत कदम उठाया हाईकमान ने

पायलट को एआईसीसी सत्र का मुख्य प्रस्ताव डैलीगेट्स के समक्ष पेश करने का मौका दिया, शशि थरुर ने प्रस्ताव को सैकण्ड किया

- अशोक गहलोत पूरे समय मंच पर उपस्थित रहे, पर, एक भी शब्द नहीं बोले दिन भर।
- पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में काफी पुराने वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणी की और कहा, जो वरिष्ठ नेता काम नहीं कर रहे, उन्हें घर बैठ जाना चाहिये तथा ''रिटायरमैंट'' ले लेना चाहिये, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि ये लोग सत्ता मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तथा अभी भी पद व जिम्मेवारी पाने के इच्छुक दिखते हैं।
- क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यंगात्मक इशारे में गहलोत भी शामिल हैं। बहरहाल, उपस्थित डैलीगेट्स ने भारी तालियाँ बजाकर व वाहवाही करके खड़गे की टिप्पणी का स्वागत किया।
- विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी, एक एससी नेता के रूप में अपना अनुभव सुनाया तथा राहुल गांधी व खड़गे ने उनके भाषण का उल्लेख किया अपने उद्बोधन में तथा राहुल गांधी ने उन्हें मंच पर बुलाने के लिये तीन-चार बार घोषणा भी करवायी, पर, जूली तब तक जा चुके थे। यह ही अनुभव प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के बारे में हुआ।
- राहुल गांधी ने यह दोहराया कि डी.सी.सी. को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है तथा डी.सी.सी. अध्यक्षों के चयन के लिए पहली बैठक 15 अप्रेल को अहमदाबाद और दूसरी 28 अप्रेल को जयपुर में आयोजित की गई है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

अहमदाबाद, 9 अप्रेल। सचिन पायलट को विशेष प्रतिष्ठा एवं तवज्जोह देने की कांग्रेस नेतृत्व की सोच के अनुरुप, पायलट से ''न्याय पथ'' पर मुख्य प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया। इस अवसर पर, एआईसीसी अधिवेशन में पहुँचे एआईसीसी डेलिगेट्स तथा कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं के समक्ष इस 12 पृष्ठ के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुये, सचिन पायलट ने एक सशक्त एवं प्रभावपूर्ण भाषण दिया।

इस प्रस्ताव का समर्थन केरल के शशि थरूर ने किया। वे, सचिन पायलट के हिन्दी भाषण के विपरीत, अंग्रेजी में बोले।

रोचक बात यह है कि जब पायलट ने भाषण दिया, उस समय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद थे, लेकिन वे पूरे दिन चुप बैठे रहे तथा मंच से कुछ नहीं बोले।

इससे ठीक पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के अंत में, वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुये, एक खुली एवं व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और कहा कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिटायर होकर घर बैठना चाहिये तथा विश्राम करना चाहिये। खड़गे की इस तीखी टिप्पणी का निशाना निश्चित रूप से गहलोत तथा ऐसे कुछ अन्य वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, जो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं तथा अब भी किसी न किसी पद की तलाश में हैं।

वहाँ एकत्रित प्रतिनिधियों ने इन टिप्पणियों का स्वागत किया व जोर से तालियाँ बजाईं।

राजस्थान से आये कई डेलिगेट्स ने भाषण दिये। खड़गे और राहुल गांधी को टीकाराम जूली का भाषण बहुत पसंद आया।

जूली ने अपने भाषण में एक घटना का जिक्र करते हुये कहा कि जब वे एक मंदिर में गये तो भाजपा नेताओं ने उस मंदिर को गंगाजल से पवित्र कराया। खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने ही अपने भाषण में इस घटना का उल्लेख किया।

भाषण के दौरान, राहुल ने जूली की तलाश में चारों ओर नजरें घुमाईं, कई बार उनका नाम लेकर पुकारा तथा पूछा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर में 25 पॉइन्ट्स की कटौती की

- डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मची खलबली से तालमेल बिठाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने रैपो रेट में मामूली कटौती की।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अप्रेल। डॉनल्ड ट्रंप के व्यापक शुल्कों से ग्लोबल इकॉनमी बुरी तरह टूट गई है, इस परिदृश्य में रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने आज अपनी बेसिक पॉलिसी ब्याज दर में 25 बेसिक पॉइन्ट की कमी की। भारी अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में पॉलिसी रेट में मामूली कटौती का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है।

लेकिन इस कदम का एक संकेत है। रैपो रेट में यह छोटी सी कटौती अब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी रणथम्भौर गये

- अधिवेशन समाप्त होने के बाद वे विमान से जयपुर पहुँचे थे।

जयपुर, 9 अप्रेल। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विमान से जयपुर रवाना हो गये।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वे रात्रि विश्राम रणथम्भौर में करेंगे तथा कल जंगल में घूमने भी जा सकते हैं।

'अब दांव पर वाणिज्य और व्यापार नहीं, वरन् आत्मसम्मान, पावर व सामरिक रणनीति है

चीन के वरिष्ठ इकॉनमिस्ट शू तिआनचेन ने पुरजोर शब्दों में कहा, टैरिफ 50 प्रतिशत हो या 500 प्रतिशत, अब फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका की ''ब्लैकमैलिंग' के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं

- पर, चीन ने हर रास्ता बंद नहीं किया है बातचीत के लिये। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ''ट्रेड वॉर (वाणिज्य व व्यापार के युद्ध में) कोई भी विजेता नहीं होता।''
- साथ में चीन ने अपने ऑफिशियल मीडिया में जनता के मनोबल के लिये यह भी कहा कि ''ट्रेड वॉर'' से कुछ पत्ते व शाखाएं जरूर टूट के गिर सकती हैं। पर, हमारी इकॉनमी का मुख्य तना, मजबूती से खड़ा रहेगा।

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 9 अप्रेल। ''यह ब्लैकमेल है'', बंदूक की गोली की तरह गूंजे इन दो शब्दों के साथ चीन ने उस समय अपना आक्रोश दर्शाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने चीन के माल पर 50 प्रतिशत का नया क्रूर टैरिफ लगाने की धमकी दी और चौबीस घंटों का अल्टीमेटम दिया।

ट्रम्प ने कहा कि यदि बीज़िंग अमेरिका के माल पर लगाया गया अपना नवीनतम 34 प्रतिशत प्रतिशोधी शुल्क वापस नहीं लेता है तो टैरिफ वॉर और अधिक तेज होगा।

दोनों पक्ष यदि पीछे नहीं हटे तो अमेरिका के बाज़ार में आने वाले चीनी माल पर चौंकाने वाला 104 प्रतिशत टैरिफ एक सच्चाई बन सकता है – एक ऐसी धमाकेदार वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप पहले से चल रहा व्यापारिक टकराव पूर्ण आर्थिक भूकंप का रूप ले सकता है।

चीन की प्रतिक्रिया साहसी, स्पष्ट व क्रोध से भरी थी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ''चीन के विरूद्ध टैरिफ बढ़ाने की अमेरिका की धमकी एक गलती के ऊपर दूसरी गलती है, जो एक बार फिर यू.एस. के ब्लैकमेल करने के स्वभाव को उजागर करती है।''

मंत्रालय ने अपने संदेश के अंत में कहा, ''यदि अमेरिका अपनी ही चलाएगा, तो चीन भी अंत तक लड़ेगा।'' फिर भी, बीज़िंग ने बातचीत के लिए दरवाजा खुला छोड़ा और विनाश के बदले ''संवाद'' को प्राथमिकता देने की बात को दोहराया तथा विश्व से ज्यादा वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि ''व्यापार युद्ध में किसी की जीत नहीं होती।''

इन शब्दों के पीछे एक तेज रणनीति छुपी है। चीन अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं खेल रहा है। वह अमेरिका की ''एकतरफा दादागिरी'' के वातावरण को राजनीतिक दृष्टि से संतुलित करने के लिए प्रतिद्वंदी विकल्प के रूप में उभरना चाहता है। सप्ताहांत के दौरान, राज्य मीडिया ने फिर से जोर दिया, नागरिकों को आश्वस्त किया कि व्यापार युद्ध शाखाओं को तो हिला सकता है लेकिन तना मजबूती से खड़ा रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख अखबार, पीपल्स डेली, में एक जोशीले संपादकीय में कहा गया ''आसमान नहीं गिरेगा।''

हालांकि ट्रंप अप्रभावित दिखते हैं। मंगलवार को बोलते हुए उन्होंने कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने बाँग्लादेश को अब तक दी जा रही ''ट्रांज़िट फैसिलिटी'' रद्द की

इस फैसिलिटी के अंतर्गत, बाँग्लादेश, भारतीय लैण्ड एण्ड कस्टम स्टेशन पर ट्रांसशिपमैंट की सुविधा का उपयोग कर भूटान और नेपाल को माल भेजा करता था

- पर, अब यह सुविधा रद्द करने के बाद, बाँग्लादेश के साथ-साथ भूटान व नेपाल को भी भारी असुविधा होगी। अतः अब भूटान व नेपाल को भारत को काफी होशियारी से समझाना होगा कि भारत का टारगैट बाँग्लादेश है, भूटान व नेपाल नहीं।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अप्रेल। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच हुई हालिया वार्ता से लगता है दोनों देशों के संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वज़ह से भारत ने बाँग्लादेश से एक प्रमुख ''ट्रांज़िट'' (पारगमन) सुविधा वापस ले ली है, जिसके जरिए बाँग्लादेश भारतीय क्षेत्र से अपना माल अन्य देशों को भेजता है। ऐसा करने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन के नियमों के उल्लंघन का खतरा है।

भारत सरकार ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी कर उस मार्ग का अवरूद्ध कर दिया, जहाँ से बाँग्लादेश भूटान व नेपाल का सामान भेजता हैं, इसमें वह भारत के लैंड कस्टम स्टेशनों से लेकर बंदरगाहों व हवाई अड्डों तक का इस्तेमाल करता है।

जो कार्गो पहले से रास्ते में हैं, उन्होंने मौजूदा प्रक्रिया के तहत बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस सुविधा को तत्काल बंद कर दिया गया है।

गत कुछ माह से भारत–पाक संबंध में काफी तनाव है और यूनुस की हालिया चीन यात्रा के बाद तो संबंध और बिगड़ गए हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा था कि भारत के लैंडलॉक्ड (चारों तरफ जमीन से घिरे) पूर्वोत्तर राज्यों के विपरीत बाँग्लादेश समुद्र तक जाने का एकमात्र द्वार है।

भारत सरकार के पारगमन सुविधाओं को वापस लेने के निर्णय को बाँग्लादेश के उस निर्णय की सीधी प्रतिक्रिया के रुप में देखा जा रहा है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपर लीक में फतेहगढ़ एसडीएम गिरफ्तार

- जयपुर से आई एसओजी टीम पकड़कर जयपुर मुख्यालय ले गई।

जैसलमेर, 9 अप्रेल (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमानाराम को बुधवार तड़के जयपुर से आई एसओजी की टीम ने पकड़ा। सूचना है कि हनुमानाराम को एस आई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पकड़ा गया है। एसओजी अब जयपुर मुख्यालय पर एसडीएम हनुमानाराम से पूछताछ करेगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जोधपुर रेंज पुलिस की टीम द्वारा 3 दिन पहले पकड़े गए पेपर लीक के सूत्रधार नरपतराम और उसकी पत्नी इंद्रा ने पूछताछ में एसडीएम हनुमानाराम का नाम लिया है। शायद इसी शक पर हनुमानाराम को एसओजी जयपुर की टीम ने पकड़ा है। अब पूछताछ के बाद ही पकड़े जाने के मामले में खुलासा हो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका गांधी की कमी खली

उनका चित्र मंच के पीछे बैकड्रॉप के रुप में जरुर था, तथा सभी डैलिगेट्स राहुल की प्रशंसा में ही जुटे रहे, तथा दो डेलिगेट्स के अलावा किसी ने प्रियंका गांधी का जिक्र भी नहीं किया

- दूसरी उल्लेखनीय बात थी, पश्चिम बंगाल पर केवल एक ही डैलिगेट बोला मंच से। क्या, यह इस बात का संकेत था, कि कांग्रेस अगले चुनाव में ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ेगी और अभी आक्रमक भाषणबाजी करके, ममता बनर्जी से बातचीत के सभी रास्ते बंद नहीं करना चाहती।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अप्रेल। सारे दिन चले अधिवेशन में बहुत सारे डेलिगेट्स ने अलग –अलग बिन्दु उठाये, लेकिन उन सभी भाषणों में एक बात सामान्य थी, और वही थी –राहुल गांधी की प्रशंसा। प्रियंका गांधी अधिवेशन में मौजूद भले ही नहीं थीं लेकिन उनका फोटो मंच की पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा था। दो वक्ताओं के अलावा, अन्य किसी वक्ता ने अपने भाषण में उनका जिक्र नहीं किया।

अपने प्रस्ताव ''न्याय पथ'' में कांग्रेस ने कहा है कि वह इंडिया गठबंधन को जारी रखने के लिये संकल्पित है तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के अपने प्रयास जारी रखेगी।

सचिन पायलट ने प्रस्ताव पेश करते हुये कहा कि कांग्रेस अपने गठबंधन को जारी रखने के लिये संकल्पित है, ताकि विभाजनकारी भाजपा–आरएसएस का सामना किया जा सके, जिन्होंने संविधान पर हमला बोला है।

जहाँ वक्फ विधेयक ने विपक्ष को एकजुट किया था, वहीं कल ''डेटा प्रोटैक्शन एक्ट'' पर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रैंस आयोजित की जा रही है। इस संबंध में इंडिया गठबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसद के अगले सत्र में, गठंधन इस मुद्दे का संयुक्त रूप से उठायेगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल का उपयोग आरटीआई को कमज़ोर करने के लिये किया जा रहा है। दरअसल, मोदी सरकार आरटीआई (सूचना का अधिकार) एक्ट को कमज़ोर करना चाह रही है।

रोचक बात यह है कि एआईसीसी अधिवेशन में पश्चिम बंगाल से केवल एक ही वक्ता थे। इससे ऐसी अटकल लगाई जा रही है कि नेतृत्व ममता बनर्जी के साथ गठबंधन के विकल्प खुले रखे हुये है। यही कारण रहा है कि अधिवेशन में ममता बनर्जी तथा तृणमूल कांग्रेस पर कोई कड़ा प्रहार नहीं किया गया। राज्य के विधानसभा चुनाव अभी एक वर्ष दूर हैं तथा पार्टी किसी भी प्रकार के समझौते की अपनी कोशिशों को लेकर आशान्वित है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अपने दो प्रिय विषयों – भाजपा–आरएसएस की ''हेट'' राजनीति और विभाजनकारी राजनीति का एजेंडा, तथा जातिगत जनगणना पर फोकस किया।

तेलंगाना, जहाँ रेवन्त रेड्डी सरकार ने जातिगत जनगणना करायी है, का उदाहरण देते हुये, राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में पिछड़े, दलित, आदिवासी लोग कूल जनसंख्या का 90 प्रतिशत है लेकिन कॉर्पोरेट्स में तथा ऊँची नौकरियों में उनका कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

---

253 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान रवाना

- ये सभी बैसाखी व खालसा दिवस मनाने जा रहे हैं तथा पाकिस्तान के सभी गुरुद्वारों के दर्शन करके लौटेंगे।

नयी दिल्ली, 09 अप्रैल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी से 253 श्रद्धालुओं के जत्थे को बैसाखी और खालसा दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान रवाना किया।

गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से अरदास करने के बाद जत्था रवाना किया गया। यह पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन करने के बाद वापस लौटेगा।

इस अवसर पर दिल्ली समिति सलाहकार परमजीत सिंह चढ़ोक ने सभी श्रद्धालुओं का सम्मान किया। समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों भी मौजूद रहे।

चढ़ोक ने बताया कि इस बार देश भर से 6751 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम पनामा कैनाल को चीन के प्रभाव से मुक्त करायेंगे'

अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह दंभपूर्ण वक्तव्य प्रतीकात्मक जरुर है, व्यवहारिक नहीं

- पहली बात तो यह है कि पनामा कैनाल न तो चीन के नियंत्रण में है और न ही अमेरिका के कंट्रोल में, और दोनों के बीच लड़ाई की जड़ वाणिज्य है न कि प्रशासनिक मैनेजमैंट।
- 31 दिसम्बर, 1999 को टोरीजोस-कार्टर संधि व समझौते के बाद, अपने पनामा की सार्वभौमिकता का सम्मान करते हुए, पनामा कैनाल पर से अपने सारे दावे स्वयं निरस्त कर दिये थे और अब उन्हें पुनः जीवित करना असंभव है।
- अब अमेरिका किसी भी कानूनी व व्यवहारिक तरीके से पनामा कैनाल का कंट्रोल प्राप्त नहीं कर सकता।
- और अभी लड़ाई कैनाल के ''फिज़िकल'' कंट्रोल के बारे में नहीं, बल्कि, दो सुपर पावर को यह जताने की है, कि किसका विश्व में प्रभाव ज्यादा है और अमेरिका अपने मित्र व गुट के देशों को यह जताना चाहता है कि वह चीन की हर चाल को ध्यान से देख रहा है और कार्यवाही कर सकता है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अप्रेल। अमेरिका के डिफैंस सैक्रेटरी ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि अमेरिका पनामा नहर को चीन के प्रभाव से वापस लेगा, तो यह बयान रणनीतिक व कूटनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया। यह बयान चीन के विश्व में बढ़ते प्रभाव के प्रति अमेरिका की चिंता को दर्शाता है, खासकर पश्चिमी गोलार्द्ध में, लेकिन यह बयान प्रतीकात्मक ज्यादा है, क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि नहर चीन के नियंत्रण में नहीं है और न ही अमेरिका के नियंत्रण में है। यह पूरी तरह से पनामा के स्वामित्व में है और वहीं इसका संचालन भी करता है।

पनामा नहर पर पनामा का नियंत्रण 31 दिसंबर 1999 से है, जब टॉरिजो–कार्टर संधियों के तहत, अमेरिका ने नहर क्षेत्र पर अपनी सभी दावों को छोड़ दिया था, जो पनामा की संप्रभुता का सम्मान करने का प्रतीक था।

हालाँकि, चीन की लिप्तता वाणिज्यिक है, न कि शासन संबंधित चीनी कंसोर्टियम, खासकर हचिसन वामपोआ, नहर के पास के बंदरगाहों–बालबोआ (प्रशांत महासागर की साइड पर) और कोलोन (अटलांटिक महासागर की साइड पर) का संचालन करते हैं, जिससे उन्हें भारी लॉजिस्टिक लाभ मिलता है। इसके अलावा बीज़िंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, पनामा में चीन का निवेश लगातार बढ़ा है। वर्ष 2017 में पनामा ने चीन के पक्ष में ताईवान से संबंध तोड़ लिए थे, जिससे बीज़िंग का क्षेत्रीय प्रभाव और मजबूत हुआ।

कानूनी दृष्टिकोण से ऐसा कोई अंतरर्राष्ट्रीय तंत्र या संधि नहीं है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को पनामा की संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना नहर को फिर से कब्जे में लेने या चीनी कंपनियों को बाहर करने की अनुमति देती हो। पनामा भी मौजूदा समीकरण बदलने की इच्छा नहीं दर्शा रहा है। कैनाल अथॉरिटी (एसीपी) पनामा में राष्ट्रीय नियंत्रण का एक गर्वित प्रतीक है, और पनामा के लोग शायद ही विदेशी शक्तियों– अमेरिका या चीन, को शर्तें निर्धारित करने की अनुमति देंगे।

व्यावहारिक रूप से, हालांकि वॉशिंगटन अधिक सूक्ष्म तरीकों से प्रभाव डाल सकता है। एक तरीका है, आर्थिक काउंटरऑफर के माध्यम से– अमेरिकी या सहयोगी देशों के बुनियादी ढांचा निवेशों का समर्थन करके, अमेरिका चीनी–निधित परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। एक अन्य रास्ता सुरक्षा साझेदारी बनाने का है, सैन्य सहयोग या खुफिया जानकारी साझा करने की पेशकश पनामा के नीति निर्माताओं को आकर्षित कर सकती है, जो रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए चिंतित हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका कूटनीतिक दबाव डाल सकता है, बहुपक्षीय मंचों या क्षेत्रीय संधियों के माध्यम से दबाव डाल सकता है, जिनका लक्ष्य पनामा की चीन की पूंजी पर निर्भरता का कम करना है।

रक्षा सचिव के शब्दों को नीति के प्रारुप के रूप में पढ़ने से बेहतर है, उन्हें रणनीतिक संकेत के रूप में समझा जाए। जैसे–जैसे चीन के साथ तनाव बढ़ रहे हैं–सेमीकंडक्टर, शिपिंग मार्ग, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और सैन्य गठबंधनों के क्षेत्रों में पनामा का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है।

असल में यह सारी चर्चा पनामा के बारे में कम और दो महाशक्तियों के बीच दबदबे के लिए चल रही प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा है। वॉशिंगटन अपने सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों से यह कह रहा है कि हम चीन की हर चाल पर नज़र रख रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पारंपरिक क्षेत्र में भी।

संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा नहर को किसी कानूनी या व्यावहारिक तरीके से वापस नहीं ले सकता। लेकिन वह चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे सकता है। सिर्फ नहर में ही नहीं, बल्कि उसके आस–पास की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)